



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 20 मार्च, 2008/30 फाल्गुन, 1929

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171002, 14 मार्च, 2008

संख्या वि०स०-लैज-गवरनमेंट बिल/1-37/2008.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक 4) जो आज दिनांक 14 मार्च, 2008 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,

गोवर्धन सिंह,
सचिव ।

**हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन
विधेयक, 2008**

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 2 का संशोधन ।
3. धारा 3 का प्रतिस्थापन ।
4. धारा 4 का संशोधन ।

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2008

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2008 है ।

2. हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (क) में, “या समान या समरूप वेतनमानों में, राज्य के भीतर अनुज्ञेय ऐसे अन्य भत्ते (अखिल भारतीय सेवा नियमों के अधीन से अन्यथा),” शब्दों, कोष्ठकों और चिन्हों का लोप किया जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

धारा 3 का प्रतिस्थापन ।

“3. वेतन.— भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने वाली तत्सम्य प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश अथवा निर्णय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य में न्यायिक अधिकारियों को अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट वेतनमान संदत्त किए जाएंगे और ऐसे अधिकारियों के भत्तों की दरें और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।” ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में, “नियम बना सकेगी” शब्दों से पूर्व “भूतलक्षी प्रभाव से” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष 1989 में ऑल इण्डिया जजिज एसोसिएशन और इसके कार्यवाहक अध्यक्ष ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सिविल) संख्या 1022/89 नामतः ऑल इण्डिया जजिज एसोसिएशन एण्ड अदरज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदरज देश भर के अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की सेवा की शर्तों में सुधार लाने के लिए अनुतोष प्राप्ति हेतु दाखिल की थी। उक्त रिट याचिका तारीख 13-11-1991 के निर्णय द्वारा निपटाई गई थी।

भारत संघ और कुछ राज्य सरकारों ने संवैधानिक प्रश्नों सहित कई आक्षेप उठाते हुए पुनर्विलोकन याचिकाएं प्रस्तुत कीं। उक्त पुनर्विलोकन याचिकाओं का, मूल निर्णय में दिए गए अनुतोष में कुछ उपान्तरण करते हुए तारीख 24-08-1993 के निर्णय द्वारा निपटारा किया गया। पुनर्विलोकन निर्णय के निदेशों के अनुसरण में भारत सरकार ने तारीख 21-3-1996 के संकल्प द्वारा न्यायमूर्ति शेडटी की अध्यक्षता में समस्त देश में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन किया। प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने 11-11-1999 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय ने तारीख 14-12-1999 के आदेश द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भारत सरकार को भेजने के निदेश दिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सी0डब्ल्यू0 पी0 संख्या 1022/89 में अपनी कार्यवाहियां जारी रखीं और उक्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, इसमें किए गए कतिपय उपान्तरणों के अध्यक्षीन, सिफारिशें स्वीकार करते हुए तारीख 21-3-2002 को निर्णय दिया जिसमें निम्नलिखित विवादक थे:-

- (क) न्यायिक अधिकारियों को संशोधित वेतनमान और एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम;
- (ख) न्यायिक अधिकारियों की नाम पद्धति बदलना;
- (ग) प्रसुविधाएं और भत्ते;
- (घ) मामलों के बैक्लॉग में कमी सुनिश्चित करना और मामलों को निपटाने की संख्या में वृद्धि करने हेतु प्रयास करना;
- (ङ) 120वीं विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना;
- (च) भरी जाने वाली रिक्तियों का बैक्लॉग ;
- (छ) न्यायिक अकादमी की स्थापना;
- (ज) उच्चतर न्यायिक सेवाओं के लिए भर्ती की पद्धति;
- (झ) उक्त निर्णय के सम्प्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालयों द्वारा समुचित नियमों की विरचना करना; और
- (ञ) न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में प्रवेश के लिए अधिवक्ता के रूप में तीन वर्ष की प्रैक्टिस को हटाना।

उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 25-11-2002 के आदेश द्वारा राज्य सरकारों को 1-04-2003 को या इससे पूर्व संशोधित वेतनमान देने के निदेश दिए। मामला हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष लाया गया जिसने 26-3-2003 को निम्नलिखित संकल्प पारित किया:—

"Keeping in view the financial position of the State which is under severe stress and the legal & constitutional aspects of the matter, this House resolves that the Government of Himachal Pradesh should not give effect to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court dated 21st March, 2002 in the matter of All India Judges Association and Others Versus Union of India and Others (Writ Petition Civil No.1022 of 1989) and subsequent order dated 25-11-2002 in the same case. This House further resolves, that State Government should refer the matter to the Government of India for initiating an appropriate administrative and legal action accordingly."

तत्पश्चात् 5-5-2003 को मामले की सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय में हुई और माननीय न्यायालय ने राज्य विधान सभा द्वारा पारित पूर्वोक्त संकल्प को गम्भीरता से लिया और राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित चिन्ता के विषय को उचित नहीं समझा। तदनुसार उन राज्यों के सभी मुख्य सचिवों और महाधिवक्ताओं को, जिन्होंने तारीख 21-3-2002 और 25-11-2002 के निर्णय/आदेश क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी नहीं की थी, को 9-05-2003 को उच्चतम न्यायालय में हाजिर होने के निदेश दिए। उक्त तारीख को राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष ब्यान दिया कि शेट्टी आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों को दो मास की अवधि के भीतर कार्यान्वित कर दिया जाएगा। तब विधान सभा ने 21-7-2003 को हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें) विधेयक, 2003 पारित किया।

अधिनियम में भत्तों के संदाय के लिए विनिर्दिष्टतः उपबन्ध नहीं किया गया था, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू नियमों द्वारा शासित थे। तथापि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 06-12-2005 के अपने आदेश द्वारा, 2002(4) एस.सी.सी. 247 के रूप में संप्रकाशित निर्णय के निबन्धनों के अनुसार अन्य बातों के साथ, राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को शेट्टी आयोग की रिपोर्ट के अध्याय-XIX में वर्णित समस्त भत्ते और प्रसुविधाएं 1-11-1999 से देने के लिए निदेश पारित किए। तत्पश्चात् तारीख 07-02-2006 के अपने आदेश में, उच्चतम न्यायालय ने रिपोर्ट के उपर्युक्त अध्याय-XIX में अभिव्यक्त विभिन्न भत्तों, सुख-सुविधाओं और अग्रिमों का उल्लेख किया तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निदेशों की, दो मास के भीतर अनुपालना करने के निर्देश दिए। माननीय

उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित उपर्युक्त निदेशों के दृष्टिगत, शेट्टी आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में मामले पर सम्यक् रूप से विचार किया गया और राज्य सरकार ने कतिपय भत्तों की बाबत तारीख 17-7-2006 को एक अधिसूचना जारी की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनः तारीख 21-11-2006 के अपने आदेश द्वारा राज्य सरकार को भत्तों/सुख सुविधाओं की बाबत पांच विनिर्दिष्ट सिफारिशों के विषय में अननुपालन के पहलुओं को जांचने के निदेश दिए और छह सप्ताह के भीतर शपथ-पत्र दाखिल करने के निदेश दिए।

राज्य विधायिका ने भारत के संविधान के अधीन अपनी विधायी शक्ति के अन्तर्गत पहले ही हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 अधिनियमित कर दिया था और राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 256 के अभिव्यक्त उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियमिति को प्रवर्तित करने के लिए विधितः आबद्ध है। हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी सेवा नियम, 2004 के नियम 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 17-7-2006 को एक अधिसूचना जारी की गई थी तथा उसमें विहित से भिन्न भत्ते और प्रसुविधाएं प्रदान करना वर्ष 2006 में यथा संशोधित पूर्वोक्त अधिनियम के अभिव्यक्त उपबन्धों के अल्पीकरण में होगा, क्योंकि वह संशोधन, "भत्तों" को उन भत्तों के रूप में परिभाषित करता है जो 31 जुलाई, 2006 को न्यायिक अधिकारियों को अनुज्ञेय थे। तदनुसार, तारीख 21-11-2006 के आदेशों के उपान्तरण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में, उपरोक्त तथ्यों और विधिक स्थिति से इसे अवगत कराने (मूल्यांकन) के लिए आवेदन किया गया था। तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के मत को उचित नहीं समझा और उक्त आवेदन को, पूर्णतः भ्रमित और न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग करार देते हुए खारिज कर दिया।

तारीख 21-11-2006 के पूर्व आदेश के निबन्धनों के अनुसार शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए दिए गए तारीख 10-01-2007 के निदेशों के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया ताकि राज्य सरकार न्यायिक अधिकारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों को भूतलक्षी प्रभाव से विनियमित करने के लिए नियम बना सके और पद "भत्ते" को पुनः परिभाषित कर सके। तदनुसार, 13-03-2007 को संशोधन विधेयक, 2007 राज्य विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया और उस पर चर्चा की गई। विधेयक को "हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, 1973" के अधीन राज्य विधान सभा द्वारा गठित प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया। प्रवर समिति ने उक्त संशोधन विधेयक, 2007 पर खण्डशः विचार करने के पश्चात् और पूर्ण संवीक्षा करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कतिपय संशोधनों की सिफारिश की:-

"(क) साम्या के हित में न्यायिक अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्ते, प्रायः राज्य में दिए जा रहे भत्तों की पद्धति के समरूप होने चाहिए ;

- (ख) केन्द्रीय नियमों को, राज्य के अधीन पदों के लिए अनुदान हस्तान्तरण पर लागू करना साध्य नहीं होगा। अखिल भारतीय सेवाओं की दशा में, संवैधानिक उपबन्ध और तद्धीन केन्द्रीय विधान ने केन्द्रीय सरकार को कतिपय नियम को बनाने के लिए प्रेरित किया। ऐसे नियम स्वयंमेव लागू नहीं किए जा सकते, जब तक कि मामला अखिल भारतीय न्यायिक सेवा इत्यादि का न हो। इसके अतिरिक्त वर्तमान में, राज्य के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जब वे भारत सरकार (बोरोइंग अथारिटी) में प्रतिनियुक्ति पर थे केन्द्रीय नियमों के अनुसार ही भत्ते प्राप्त कर रहे थे न कि राज्य सरकार के।
- (ग) वेतनमानों को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जा सकता है पर भत्तों को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करने का चलन नहीं था, विशिष्टतया उन भत्तों को, जो विनिर्दिष्ट प्रकृति के व्ययों के मुजरा (कटौती) की प्रतिपूर्ति की प्रकृति के थे।”

उपरोक्त के अध्यक्षीन समिति सहमत थी, कि सरकार को अधिसूचना जारी करके, न्यायिक अधिकारियों को उपयुक्त भत्ते प्रदान करने का प्राधिकार दिया जाए। समिति ने विनिश्चय किया कि इसके समक्ष रखे गए विधायी प्रस्ताव को, समान या समरूप वेतनमानों, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं, में राज्य के भीतर अनुज्ञेय ऐसे अन्य भत्तों (अखिल भारतीय सेवा नियमों के अधीन से अन्यथा) को प्रदान करना अनुमत कर, तदनुसार उपान्तरित किया जाए।

प्रवर समिति की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा गया और 27-08-2007 को इसे स्वीकार किया गया। प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए विधेयक को राज्य विधान सभा द्वारा उसी दिन पारित कर दिया गया। विधेयक पर 21-09-2007 को महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमति दी गई और इसे 2007 का अधिनियम संख्यांक 16 के रूप में 26-09-2007 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

इसी मध्य, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन ने माननीय उच्चतम न्यायालय में, 1989 की सी0 डब्ल्यू0 पी0 संख्या 1022, में अवमानना याचिका दाखिल की जिसमें प्रतिवादी/राज्य, वरिष्ठ सरकारी कृत्यकारियों द्वारा आदेशों की साशय और जानबूझकर अवज्ञा का अभिकथन किया और माननीय मुख्यमन्त्री को प्रतिवादी के रूप में अभियोजित किया और निम्नलिखित प्रभाव का अनुतोष चाहा:-

- “(i) यह कि समस्त प्रतिवादी इस माननीय न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप में हाजिर होकर शेड्यूल आयुग की रिपोर्ट की अननुपालना की तथा समय-समय पर इस माननीय न्यायालय के विशिष्ट और आबद्ध निर्देशों की बाबत स्थिति स्पष्ट करें;
- (ii) यह कि दोषी पाए गए प्रतिवादियों को इस माननीय न्यायालय की अवमानना के लिए दण्डित किया जाए;
- (iii) कोई अन्य राहत जिसे इस माननीय न्यायालय द्वारा आवेदन को अनुज्ञात करते हुए न्याय के हित में उचित समझा जाए”।

पूर्वोक्त अवमानना याचिका की मूल रिट याचिका सहित 23-10-2007 को सुनवाई हुई और कार्यवाहियों के दौरान याचिकाकर्ता एसोसिएशन के अधिवक्ता ने उसे वापिस लेने की अनुमति मांगी। याचिका वापिस ली गई के रूप में खारिज कर दी गई और शेट्टी आयोग की सिफारिशों की बाबत माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:—

".....The Learned Amicus Curiae will prepare a chart/questionnaire indicating the various items of benefits/perquisites extended to the Judicial Officers serving, retired as well as those who were/are on deputation, and also indicate therein the dates from which such benefits have been given effect. Copies thereof shall be given to the respective counsel of the States/Union Territories within a period of two weeks. The States/ Union Territories shall file their reply thereto in the form of an affidavit within a period of three weeks thereafter, indicating therein all the information relating to the perquisites/benefits extended to the Judicial Officers and the dates from which such benefits were extended."

तारीख 23-10-2007 के पूर्वोक्त आदेशों के क्रम में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए0टी0एम0 सम्पत से इस पर प्रतिक्रिया की बाबत प्रश्नावली/चार्ट प्राप्त हुआ जिसका उत्तर, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, वित्त और स्वास्थ्य विभागों से एकत्रित सूचना के आधार पर, तारीख 1-12-2007 और 14-12-2007 के शपथ-पत्रों द्वारा सम्यक् रूप से दिया गया।

पूर्वोक्त संशोधन अधिनियम, 2007 अभी भी राज्य सरकार को शेष भत्तों को प्रदान करना अनुज्ञात नहीं करता क्योंकि वे, समान और समरूप वेतनमानों में राज्य सरकार के अन्य प्रवर्गों के कर्मचारियों को भी सुसंगत समय में यथा पुरःस्थापित विधेयक में यथा परिकल्पित भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया ताकि उन प्रसुविधाओं/भत्तों को, जिनको देने के बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने निदेश दिया था परन्तु जिन्हें 17-7-2006 की अधिसूचना द्वारा नहीं दिया गया था, प्रदान किया जा सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख 2008.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2, 3 और 4 के सामर्थ्यकारी उपबन्धों के अनुसरण में यदि शेट्टी आयोग की शेष सिफारिशों पर भत्ते दे दिए जाते हैं तो वार्षिक अतिरिक्त आवर्ती व्यय लगभग 97,77,000 /— (सत्तानवे लाख सतहत्तर हजार) रूपए होगा। इसके अतिरिक्त यदि शेट्टी आयोग की सिफारिशों पर अग्रिम / ऋण दिए जाते हैं तो वार्षिक 1,00,00,000 /— (एक करोड़) रूपए का व्यय प्रत्याशित है। यदि उच्चतम न्यायालय के निदेश पर शेट्टी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भत्ते भूतलक्षी प्रभाव से दे दिए जाते हैं तो 1-11-1999 से भूतलक्षी अनुदान के मददे कुल व्यय लगभग 2,55,23,000 /— (दो करोड़ पचपन लाख तेईस हजार) रूपए होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4 राज्य सरकार को न्यायिक अधिकारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। इस प्रत्यायोजन का उपबन्ध सी0डब्ल्यू0पी0 संख्या 1022 / 1989 नामतः ऑल इण्डिया जजिज एसोसिएशन एण्ड अदरज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदरज में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6-12-2005 के आदेश के कारण किया जा रहा है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या: गृह-बी (जी)4 / 95-वॉल्यूम-III)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2008 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2008

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

जे० एन० बारोवालिया,
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : 2008

**THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL OFFICERS (PAY, ALLOWANCES AND
CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 2008**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Substitution of section 3.
4. Amendment of section 4.

THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL OFFICERS (PAY, ALLOWANCES AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 2008

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 (Act No. 13 of 2003).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Amendment Act, 2008.

Amend-
ment of
section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in clause (a), the words, brackets and signs “admissible within the State (other than under All India Service Rules), in indential or similar scale of pay,” shall be deleted. 13 of 2003

Substi-
tution of
section 3.

3. For section 3 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“3. Salaries.— Notwithstanding anything contained in any rules made under any other law for the time being in force, regulating the pay, allowances and other conditions of service, or any order or judgment passed by any court, the Judicial Officers in the State shall be paid the pay scales as specified in the Schedule and the rates of allowances and other conditions of service of such Officers shall be such as may be prescribed.”.

Amend-
ment of
section 4.

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), after the words “make rules”, the words “with retrospective effect” shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the year 1989, the All India Judges Association and its working President, filed Writ Petition (Civil) No. 1022/89 titled as All India Judges Association & Ors. Vs. Union of India & Ors. before the Hon'ble Supreme Court of India under Article 32 of the Constitution of India seeking reliefs so as to improve the conditions of service of subordinate judicial officers all over the country. The said writ petition was disposed off by the judgment dated 13-11-1991.

The Union of India and some State Governments preferred review petitions raising several objections, including constitutional questions. The said review petitions were disposed off vide judgment dated 24-8-1993, modifying some of the reliefs given in the original judgment. In pursuance to the directions in the review judgment, Government of India by a resolution dated 21-3-1996 constituted the First National Judicial Pay Commission for the subordinate judiciary all over the country, under the chairmanship of Mr. Justice Shetty. The First National Judicial Pay Commission submitted its report to the Govt. of India on 11-11-1999. The State Governments and Union Territories were directed by the Supreme Court *vide* order dated 14-12-1999 to send their responses to the Union of India on the same. The Hon'ble Supreme Court continued with its proceedings in CWP. No. 1022/89 and after considering the recommendations made by the said Commission, delivered judgment dated 21-3-2002, accepting the recommendations subject to certain modifications made therein, which related to the following issues:—

- (a) Revised Pay Scales and Assured Career Progression Scheme to the Judicial Officers;
- (b) Change of Nomenclature of the Judicial Officers;
- (c) Benefits and allowances;
- (d) Ensuring decrease in backlog of cases and efforts to increase disposal of cases;
- (e) Increase in the Judges strength on the basis of 120th Law Commission Report;
- (f) Backlog of vacancies to be filled;
- (g) Establishment of the Judicial Academy.
- (h) Mode of recruitment to Higher Judicial Services;
- (i) Framing of appropriate Rules by the High Courts in light of the observations in the said judgment; and
- (j) Doing away with three years practice as an Advocate for entry into Judicial Service as Civil Judge (Junior Division).

The Supreme Court *vide* its order dated 25-11-2002 directed the State Governments to implement the revised pay scales on or before 1-4-2003. The matter came up in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha which passed the following Resolution on 26-03-2003 :—

“Keeping in view the financial position of the State which is under severe stress and the legal & constitutional aspects of the matter, this House resolves that the Government of Himachal Pradesh should not give effect to the Judgment of the Hon’ble Supreme Court dated 21st March, 2002 in the matter of All India Judges Association and Others Versus Union of India and Others (Writ Petition Civil No.1022 of 1989) and subsequent order dated 25.11.2002 in the same case. This House further resolves, that State Government should refer the matter to the Government of India for initiating an appropriate administrative and legal action accordingly.”

The matter was thereafter listed in the Hon’ble Supreme Court on 5-5-2003 and the Hon’ble Court took a serious view of the aforesaid resolution passed by the State Legislative Assembly and did not appreciate the concern of the State Government regarding the financial scenario. Accordingly, all the Chief Secretaries and Advocate Generals of the States who had not issued the notification with regard to the implementation of the Judgment/order dated 21-3-2002 and 25-11-2002 were directed to put in appearance on 9-5-2003. On the said date the Ld. Advocate General for the State stated before the Hon’ble Court that within a period of two months the pay scales as recommended by the Shetty Commission shall be implemented. Vidhan Sabha then passed the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Bill on 21-7-2003.

The Act did not provide specifically for payment of allowances which were governed by rules applicable to State Government employees. However, the Hon’ble Supreme Court of India *vide* its order dated 6-12-2005 passed directions *interalia* to the States/Union Territories to release all the allowances and benefits enumerated in Chapter-XIX of the Shetty Commission Report w.e.f. 1-11.1999 in terms of the Judgment reported as 2002 (4) S.C.C. 247. Subsequently in its order dated 7-02-2006, the Supreme Court mentioned the various allowances, amenities and advances figuring in aforesaid Chapter-XIX of the Report and various States/ Union Territories were directed to comply with the directions within two months. In view of the aforesaid directions passed by the Hon’ble Supreme Court, from time to time, the matter in relation to recommendations of Shetty Commission was duly considered and the State Government issued a notification dated 17-07-2006 in respect of certain allowances. The Hon’ble Supreme Court again *vide* its order dated 21-11-2006 directed the State Government to look into the aspects of non-compliance regarding five specific recommendations *qua* the allowances/amenities and file the affidavit within six weeks.

The State Legislature within the realm of its legislative power under the Constitution of India had already enacted the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 and the State Government is legally bound to enforce the said enactment in view of the express provision of article 256 of the Constitution. In exercise of powers conferred by rule 7 of the Himachal Pradesh Judicial Services Rules, 2004, a notification dated 17-07-2006 had been issued, and the grant of allowances and benefits other than those prescribed therein would be in derogation to the express provisions of the Act *ibid* as amended in the year 2006, since that amendment defines ‘allowances’ as those allowances that were admissible to Judicial Officers as on 31st July, 2006. Accordingly, an application for modification of the orders dated 21-11-2006 was preferred in the Hon’ble Supreme Court, apprising it of the aforesaid facts and legal position. However, the Apex Court did not appreciate the contention of the State Government and dismissed the said application terming it as an abuse of the process of the Court and being wholly misconceived.

As a consequence of the directions dated 10-01-2007 directing the filing of an affidavit in terms of the previous order dated 21-11-2006, it was decided to suitably amend the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, allowances and Conditions of Service) Act, 2003 in order to empower the State Government to make rules with retrospective effect regulating Pay, Allowances and Conditions of Service of the Judicial Officers and to redefine the expression “Allowances”. Accordingly, the Amendment Bill, 2007 was introduced in the State Legislative Assembly on 13-3-2007 and discussed. The Bill was referred to the Select Committee constituted by the State Legislative Assembly under the “Rules of Procedure and Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973”. The Select Committee after deliberating upon the said Amendment Bill, 2007 clause by clause and after thorough scrutiny recommended certain amendments in its Report stating interalia as follows:—

- “(a) In the interest of equity the allowances to be given to Judicial Officers should be generally in line with the pattern of allowances being given within the State;
- (b) It may not be feasible to apply Central Rules on transfer grants to posts under the State. In the case of All India Services, the Constitutional provision and Central Legislation thereunder had led to formulation of certain rules by the Central Government. Such rules could not be applied *ipso-facto*, unless it was a case of an All India Judicial Service etc. Moreover at present, All India Service Officers of the State were getting allowances as per Central Rules only when they went on deputation to Government of India (borrowing authority) not the State Government.
- (c) While pay scales could be revised retrospectively, it was normally not a practice to revise allowances retrospectively, particularly allowances which were in the nature of reimbursement of off setting of expenditures of specified natures.

Subject to the above, the Committee agreed that Government may be given the authority to grant suitable allowances to the Judicial Officers through issuance of notification. The Committee decided that the legislative proposal placed before it may be modified accordingly by allowing grant of such other allowances admissible within the State (other than under All India Service Rules) in identical or similar scales of pay, as may be notified by Government from time to time.

The report of the Select Committee was laid on the table of the House and adopted on 27-8-2007. The Bill as reported by the Select Committee was passed by the State Legislative Assembly on the same day. The Bill was assented to by H.E. the Governor on 21-9-2007 and published in the Rajpatra on 26-9-2007 as Act No.16 of 2007.

In the meantime, the Himachal Pradesh Judicial Officers Association filed a contempt petition in the Hon'ble Supreme Court in the CWP No.1022 of 1989, alleging intentional and wilful defiance of the orders by the Respondent/State, senior Government functionaries and the Hon'ble Chief Minister were impleaded as respondents seeking relief to the following effect:—

- “...(i) That all the respondents to appear in person before this Hon'ble Court to explain their position regarding non-implementation of the Shetty Commission Report as also the specific and binding directions of this Hon'ble Court from time to time;
- (ii) That the respondents found guilty may be punished for contempt of this Hon'ble Court;
- (iii) any other relief as deemed fit by this Hon'ble Court in the interest of justice, by allowing the application.....”.

Aforesaid contempt petition was listed for hearing on 23.10.2007 alongwith the main writ petition and during the course of proceedings, the counsel of the Petitioner Association sought permission to withdraw the same. The petition was dismissed as withdrawn and with respect to the Shetty Commission recommendations, following orders were passed by the Hon'ble Supreme Court:—

“.....The Learned Amicus Curiae will prepare a chart/questionnaire indicating the various items of benefits/perquisites extended to the Judicial Officers serving, retired as well as those who were/are on deputation, and also indicate therein the dates from which such benefits have been given effect. Copies thereof shall be given to the respective counsel of the States/Union Territories within a period of two weeks. The States/ Union Territories shall file their reply thereto in the form of an affidavit within a period of three weeks thereafter, indicating therein all the information relating to the perquisites/benefits extended to the Judicial Officers and the dates from which such benefits were extended.”

In continuation of aforesaid orders dated 23-10-2007 questionnaire/ chart was received from Sh.A.T.M. Sampath, Senior Advocate Supreme Court of India seeking response thereto, which was duly replied to by way of affidavits dated 1-12-2007 and 14-12-2007 based on the information gathered from the Registrar General, High Court, Finance and Health Departments.

As the aforesaid Amendment Act of 2007 still does not permit the State Government to grant the remaining allowances since they are not being given to other categories of State Government employees in identical or similar scales of pay nor with retrospective effect as envisaged in the Bill as introduced at the relevant time, hence, it has been decided to amend the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 suitably so as to enable the grant of benefits/allowances as directed by the Hon'ble Supreme Court but not given in the notification dated 17-7-2006.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Shimla:

The.....2008.

FINANCIAL MEMORANDUM

In case the remaining Shetty Commission recommendations on allowances are given pursuant to the enabling provision of clauses 2, 3 and 4 of the Bill, the annual additional recurring expenditure will be approximately Rs. 97,77,000/-. In addition in case advances/loans are given as per Shetty Commission recommendations, an annual expenditure of Rs.1,00,00,000/- is anticipated. In case the allowances as per Shetty Commission report are given retrospectively as per Supreme Court directions, the total expenditure from 1-11-1999 onwards on account of the retrospective grant will be approximately Rs. 2,55,23,000/-.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules regulating Pay, Allowances and Conditions of Service of the Judicial Officers with retrospective effect. This delegation is being provided because of the order of the Supreme Court dated 6-12-2005 in CWP. No. 1022/1989 titled as All India Judges Associations and others. Vs. Union of India and others. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

**RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE
207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA**

(File No.Home-B(G)4/95-Vol-III)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Amendment Bill, 2008, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

**THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL OFFICERS (PAY,
ALLOWANCES AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT
BILL, 2008.**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions
of Service) Act, 2003 (Act No.13 of 2003).*

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

J. N. BAROWALIA,
Principal Secretary (Law).

Shimla:

The, 2008.

